2	3	4	5	6
12. Madhya Pradesh	31197.24	15243.75	34339.59	15243.75
13. Maharashtra	26839.28	10217.50	29542.68	10217.50
14. Manipur	413.36	0.00	413.36	0.00
15. Meghalaya	483.68	0.00	483.68	0.00
16. Mizoram	203.75	0.00	203.75	0.00
17. Nagaland	518.46	0.00	518.46	0.00
18. Orissa	19972.66	7143.75	21994.43	7143.75
19. Punjab	1634.30	0.00	1699.28	0.00
20. Rajasthan	12961.33	4568.75	14266.86	4568.75
21. Sikkim	188.76	0.00	188.76	0.00
22. Tamil Nadu	22256.18	3255.00	24497.94	3255.00
23. Tripura	536.90	0.00	536.90	0.00
24. Uttar Pradesh	59998.40	8335.00	66041.76	8335.00
25. West Bengal	22063.20	6125.00	24285.53	6125.00
26. A & N Islands	152.70	0.00	152.70	0.00
27. D & N Haveli	82.89	0.00	82.89	0.00
28. Daman & Diu	48.83	0.00	48 83	0.00
29. Lakshadweep	76.55	0.00	76.55	0.00
30. Pondicherry	149.47	0.00	149.47	0.00
TOTAL :	318122.39	87820.00	349872.40	87820.00

* Includes allocation for Indira Awads Yojna (JAY) and million wells scheme (MWS) which are the two sub-schemes of JRY.

मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के लिए आवासीय यूनिटों का निर्माण

5995. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों के लिए बनायी गयी आवासीय यूनिटों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या सरकार वर्ष 1994 के दौरान और आवासीय यूनिटों का निर्माण किए जाने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इन्दिरा आवास योजना, जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना है, के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों को निशुल्क मकान उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 1993–94 से इंदिरा आवास योजना को गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए भी इस शर्त के आधार पर लागू किया गया है कि इन्दिरा आवास योजना के आवंटन का अधिकतम 40 प्रतिशत अंश गैर-

अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिए मकान बनाने पर खर्च किया जाएगा। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत जिला-वार बनाए गए मकानों की निगरानी केन्द्रीय स्तर पर नहीं की जाती है। तथापि, 1991–92 से 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानो की संख्या
1991–92	40644
1992–93	47156
1993–94	48108

(ख) जी, हां।

मध्य प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास योजनायें/परियोजनायें

5996. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी ग्रामीण विकास योजनायें और परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं और उन का जिलेवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन योजनाओं/परियोजनाओं पर जिलेवार कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के **(ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एम० पटेल)** : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और भूमि सुधार के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिये स्वीकृति हेतु लंबित ग्रामीण विकास परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

1. **जवाहर रोजगार योजना**

विशेष और अभिनव परियोजनाओं से संबंधित जवाहर रोजगार योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खारगांव जिले के बरवानी खण्ड में बापनगजा पहाड़ियों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने नामक एक परियोजना स्वीकृति हेतु लंबित है। जांच समिति की जब कभी चालू वर्ष के दौरान बैठक होगी तब इस परियोजना पर विचार किया जाएगा।

2. **त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम :**

मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त निम्नलिखित चार योजनायें विचाराधीन हैं :–

(1) मोरेरा जिले में करहाल खण्ड के लिये जल संरक्षण एवं संपूर्ति परियोजना।

(2) राजगढ़ जिले में समेकित जल संपूर्ति जल संरक्षण परियोजना।

(3) धार जिले के लिये जल संरक्षण एवं संपूर्ति परियोजना।

(4) शाजापुर जिले के लिये जल संरक्षण परियोजना।

उपरोक्त परियोजनाओं की स्वीकृत करने हेतु शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

3. **भूमि सुधार :**

मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त निम्नलिखित दो परियोजनायें विचाराधीन हैं :–

(1) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति और निधियों को रिलीज हेतु 541.46 लाख रुपये की लागत वाला एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(2) चार जिलों अर्थात सीधी, विदिशा होशंगाबाद और बिलासपुर के लिये 114.50 लाख रुपये की लागत वाला भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक प्रस्ताव भूमि